सशक्तीकरण से संवृद्धि

चरण सिंह

भारत की गिनती दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में होती है। कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग तक उसका लाभांश पहुंच न जाए। उसी को ध्यान में रखकर समाज के हर वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए अनेकानेक कदम उठा रही है। कृषक, छात्र, उद्यमी, कारोबारी आदि सभी को एक समान वित्तीय मंच पर लाने का यह प्रयास अभी शुरुआत पर है परंतु संकेत अच्छे दिख रहे हैं

मई 2014 के बाद से केंद्र सरकार देश को सबल बनाने और विकास दर को 9 प्रतिशत से अधिक करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद सरकार ने अनेक घोषणाएं कीं जिनके केंद्र में विकासोन्मुखी नीतियों के माध्यम से विकास की उच्च दर प्राप्त करना था। लगभग आठ शताब्दियों तक विदेशी शासन के अंतर्गत भारत ने संसाधनों के अभाव और आर्थिक विकास की निम्न दर (प्रति व्यक्ति) जैसी समस्याओं का सामना किया है। 1951 में देश की 53 प्रतिशत आबादी (20 करोड़ लोग) गरीबी रेखा से नीचे रहने को विवश थे। भारत एक निम्न आबादी वाला देश माना जाता था। आजादी के बाद के दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई जहां समाजवादी अवधारणा प्रबल थी। अनेक प्रकार की योजनाओं और नीतिगत उपायों के बाद, जिनमें से कुछ गंभीर संकट के कारण स्वीकृत किए गए थे, भारत बीसवीं सदी के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। तत्पश्चात् 2015 के बाद से भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती विकास अर्थव्यवस्था बना है। यहां संशोधित और उच्च मानकों के बावजूद गरीबी का स्तर कम हुआ है। अब देश की 30 प्रतिशत आबादी निर्धन है। अगले 5 वर्षों में देश की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

वैसे भारत के विकास की कहानी बहुत रोचक है और आर्थिक इतिहास अप्रत्याशित रहा है। एक समय वह भी था जब देश के विकास में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम थी और सेवा क्षेत्र की अधिक। दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत के साथ स्थिर बनी हुई थी। विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि औद्योगिक आधार मजबूत किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने मई, 2014 में पद ग्रहण करने के तत्काल बाद *मेक इन इंडिया* अभियान का शुभारंभ किया।

विकास दर हासिल करने और औद्योगिक आधार सुनिश्चित करने के लिए अन्य कारकों के अतिरिक्त वित्त की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विकास के प्रारंभिक चरणों में बैंकिंग प्रणाली उल्लेखनीय भूमिका निभाती है इसलिए न केवल बैंकिंग संस्थाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया बल्कि यह सुनिश्चित भी किया गया कि बैंकिंग प्रणाली की पैठ बने और उन लोगों को वित्तीय संसाधन आसानी से उपलब्ध हों जिन्हें उनकी जरूरत है। फिर वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें कारोबार करना सहज हो और जहां जरूरत हो, वहां हैंड होल्डिंग भी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद सरकार ने क्रमिक ढंग से मुद्रा बैंक, स्टार्ट अप और स्टैंड अप, अटल नवाचार मिशन जैसी योजनाओं की घोषणा की।

यह समझना भी जरूरी है कि हालांकि भारत दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और यहां की जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी उनका पूरी तरह से दोहन अभी नहीं किया गया है। भारत को अगले एक दशक में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 11 करोड़ अवसर पैदा करने की जरूरत है क्योंकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या तब तक श्रमशील आयु वर्ग में

लेखक आईआईएम बंगलुरु में इकोनॉमिक्स के आरबीआई चेयर प्रोफेसर हैं। इससे पहले वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: charansingh60@gmail.com

पहुंच जाएगी। भारत की श्रमशक्ति 2022 तक एक अरब तक हो जाएगी। इसलिए बेरोजगारी के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की सामाजिक अशांति से बचने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के लिए रोजगार सृजित किए जाएं। आजादी के बाद के नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में सरकार मुख्य रूप से बढ़ती श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन बाद के वर्षों में निजी क्षेत्र ने भी योगदान देना प्रारंभ किया। फिर भी 2012 तक देश की 90 प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत थी। भविष्य में सालाना लगभग 1.11 करोड़ नौकरियां देने के लिए रोजगार सृजन करने वालों और उद्यमियों की भी जरूरत होगी। सिर्फ रोजगार तलाश करने वालों से काम नहीं चलेगा।

बैंकों की भूमिका

स्थिर विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग में मजबूत वित्तीय प्रणाली जरूरी है। जिससे उत्पादक निवेश के साथ बचतकर्ताओं से निवेशकों तक संसाधनों का कारगर आवंटन प्रभावकारी हो। बैंक दरअसल एक एसेट ट्रांसफॉरमेशन का काम करते हैं जहां एक जमाकर्ता संसाधनों को बैंक में जमा करता है और बैंक बदले में बाजार को उधार देता है। बैंक अर्थव्यवस्था में गरीबी कम करने का काम भी करते हैं। विकास को सहज बनाते हैं और वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार की वित्तीय प्रणाली से आय असमानता कम होती है क्योंकि इसके तहत पूंजी का प्रवाह उन उद्यमियों तक होता है जिनके पास धन का अभाव होता है।

बैंकिंग की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार को यह आशंका थी कि देश की बैंकिंग परिसंपत्तियों पर कुछ व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण हो सकता है। साथ ही बैंकों के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास हासिल करना था। इसलिए सरकार ने पहले 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों और फिर 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद से भारत की बैंकिंग प्रणाली में रचनात्मक परिवर्तन आया। सरकार कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने लगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समाज के वंचित समूहों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गईं। 2011 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि देश में 24.7 करोड़ परिवारों में से केवल 14.5 करोड़ परिवारों (58.7 प्रतिशत) की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 16.9 करोड़ परिवारों में से केवल 8.1 करोड़ परिवार (54.5 प्रतिशत) ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं।

अगस्त 2014 में सरकार ने पीएमजेडीवाई का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग और जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा और किफायती तरीके से पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो। पीएमजेडीवाई के तहत 27 अप्रैल, 2016 तक 21.7 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जोकि 31 मार्च, 2014 तक सभी वाणिज्यिक बैंकों में 122 करोड़ मौजूदा खातों की तुलना में एक लंबी छलांग कही जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 17.9 करोड़ खातों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 9.7 करोड़ खाते आधार से जोड़े गए हैं और इनमें 83.6 प्रतिशत परिचालित भी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20.12 करोड़ खाते हैं जिनमें से 9.8 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में हैं। सबसे अधिक खाते उत्तर प्रदेश (3.3 करोड़) में खोले गए हैं। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। इनमें से प्रत्येक राज्य में 2 करोड़ खाते खोले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पहल के बाद 95 प्रतिशत से अधिक परिवारों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक हुई है।

बैंकिंग की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार को यह आशंका थी कि देश की बैंकिंग परिसंपत्तियों पर कुछ व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण हो सकता है। साथ ही बैंकों के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास हासिल करना था। इसलिए सरकार ने पहले 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों और फिर 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

पीएमजेडीवाई को जैम ट्रिनिटी यानी अर्थात जन धन योजना-आधार-मोबाइल नंबर में भी शामिल किया गया है जिसके केंद्र में एक लक्षित तरीके से गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है। जाम के तहत तकनीकी विकास और प्रक्रियाओं के मानकीकरण के जरिए बैंक शाखा तक बिना जाए भी मोबाइल फोन की मदद से बैंकिग सेवा प्राप्त की जा सकती है। यहां तक कि ऋण भी हासिल किया जा सकता है।

मुद्रा बैंक और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

8 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक की शुरुआत की जिसके केंद्र मे छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है। देश में लगभग छह करोड़ उद्यमी मौजूद हैं जोकि व्यक्तिगत उद्यमी हैं और छोटी विनिर्माण इकाई चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इनमें से केवल 4 प्रतिशत को संस्थागत वित्त प्राप्त होता है। 10 लाख रुपये तक की वित्तीय जरूरतों वाली सूक्ष्म इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रा बैंक इन इकाइयों के लिए नियामक और पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करेगा। साथ ही उन्हें विकसित होने में सहायता प्रदान करेगा। मुद्रा बैक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों को लागू करेगा जिससे लघु स्तर के उद्यम धोखा न खाएं और देश में प्रचलित मानक दरों से अधिक भुगतान न करें।

9 मई, 2015 को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन योजनाओं की शुरुआत की। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना नामक इन योजनाओं को बैंकिंग खातों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन योजनाओं से बैंकिंग उद्योग में कारोबार बढ़ेगा और वित्तीय समावेशन वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनेगा।

स्टैंड अप और स्टार्ट अप

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अप्रैल में समाज के विशेष रूप से वंचित वर्गों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय

SR -2908 -YOJANA-MAG- JUNE 2016 64 PAGE BOOK- SIZE-195 X 272.job FORM 1 SIDE A DATE 05/20/2016 TIME 21:22:51

बजट में सरकार ने देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने और सशक्त करने के लिए कई उपाय किए जैसे संसाधनों का आवंटन, कौशल कार्यक्रमों का प्रारंभ, कर रियायतें प्रदान करना और कारोबार करना सुविधाजनक बनाना। बजट घोषणाओं और तत्पश्चात प्रारंभ की गई योजनाओं का उद्देश्य जनवरी में शुरू किए गए स्टार्ट अप को मजबूती प्रदान करना है, जिससे देश में रोजगार सृजन की गति मिले।

चुनौतियां

सरकार के प्रयासों के परिणाम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अनेक चुनौतियां हैं। वित्त तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करते हुए उच्च विकास दर हासिल करने हेतु इन चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है।

ब्याज दर का मुद्दा

यह समझना जरूरी है कि हालांकि साहूकार मोटा ब्याज वसूलते हैं लेकिन फिर भी उधार लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों की अनदेखी करते हुए उन्हीं के पास जाते हैं, भले ही बैंक उनके कितने ही पास क्यों न हो। इसलिए इस बात पर अध्ययन किया जाना चाहिए कि अधिक ब्याज लेने के बावजूद साहूकारों का धंधा फलता-फूलता कैसे है। इसका मतलब यह भी है कि उधार लेने के फैसले को ब्याज दरें प्रभावित नहीं करती। जैसा कि साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि चाणक्य की ब्याज दर संरचना जोखिम भरी थी और ब्याज की दर उधारकर्ता के कारोबार में शामिल जोखिम के साथ बढ़ती थी। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में सामान्य अग्रिम के लिए प्रति वर्ष 15 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता था लेकिन व्यापारियों को दिए गए उधार का ब्याज 60 प्रतिशत होता था। अगर माल को जंगल से ले जाया जाता था तो व्यापारियों को 120 प्रतिशत ब्याज देना होता था। जबकि आयात-निर्यात करने वाले व्यापारियों को सालाना 240 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता था।

वित्तीय समावेश

पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए नए खातों के परिचालन को सुधारने और लेन-देन बढ़ाने हेतु आत्मविश्वास बढ़ाने तथा बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिससे माहौल में भी सुधार हो। निम्न आय या परिसंपत्ति की होल्डिंग, वित्तीय उत्पादो के संबंध में जागरूकता की कमी, लेन-देन की उच्च लागत, असुविधाजनक उत्पाद जिनका वहन नहीं किया जा सकता या जो लचीले नहीं हैं, जोकि ग्रामीण और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के अनुसार नहीं हैं, जैसे कारक वित्तीय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने में बाधक होते हैं।

बैंकिंग सुविधा को ग्रामीण और वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक एटीएम लगाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए साहूकार कम से कम दूरी पर होते हैं लेकिन बैंकों तक पहुंचने में समय लगता है। देश में 6 लाख गांवों में सिर्फ 50,000 गांवों में ही किसी बैंक की शाखा है।

अगस्त 2014 में सरकार ने पीएमजेडीवाई का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग और जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा और किफायती तरीके से पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो। पीएमजेडीवाई के तहत 27 अप्रैल, 2016 तक 21.7 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जोकि 31 मार्च, 2014 तक सभी वाणिज्यिक बैंकों में 122 करोड़ मौजूदा खातों की तुलना में एक लंबी छलांग कही जा सकती है।

मुद्रा बैंक

सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण देने के लिए, विशेषकर उन गतिविधियों के लिए जो मुद्रा बैंक के तहत आती हैं, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक सूक्ष्म इकाइयों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनें और इस क्षेत्र को ऋण देने हेतु अनुकूल माहौल बनाया जाए।

स्टैंड अप और स्टार्ट अप

इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें उद्यमियों का सृजन हो। भारत को अब उद्यमशीलता के लिए विश्व स्तरीय संस्थानों और पाठ्यक्रमों पर विचार करने की जरूरत है: संभवत: आईआईटी, आईएमएम और कृषि विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भारतीय उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा नीति को देश में अधिक विश्वस्तरीय कॉलेजों की स्थापना पर जोर देना चाहिए जो वाणिज्य, विधि और बिजनेस स्टडीज में विशेषज्ञता प्राप्त हों।

देश में रोजगारपरक श्रम की कमी के मुद्दे पर भी तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के अपने विश्लेषण के अनुसार, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा कॉलेजों से सालाना ग्रेजुएट होने वाले 120 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 10 प्रतिशत में श्रमशक्ति में शामिल होने लायक दक्षता होती है।

वैसे परिवार के सदस्य, मित्र और यहां तक कि शिक्षक भी उद्यमशीलता में जोखिम और संदेह को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके अलावा, भारतीय मूल्य ऐसे हैं कि इसमें नाकामी के प्रति सहनशीलता न के बराबर है। दूसरी ओर सिलिकॉन वैली में निवेशक ऐसे उद्यमियों की मदद करने के अधिक इच्छुक रहते हैं जो अपने पहले प्रयास में, और यहां तक कि कम से कम दो बार असफल रहे हों। जोखिम झेलने के लिए एक फॉलबैक व्यवस्था जरूरी है इसलिए सरकार को असफल रहने वाले उद्यमियों को किसी किस्म की सामाजिक सुरक्षा या बीमा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

उद्यमियों की सफलता के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु, सरकारी मंजूरियों में विलंब नहीं होना चाहिए। 1982 से मौजूदा 110 इनक्यूबेटर्स के साथ, सालाना केवल 500 स्टार्ट अप्स को बढ़ावा दिया गया और तब से केवल 40,000 तकनीकी नौकरियों का सृजन हो पाया है और अंतत: उद्यमशीलता को पोषित करने के लिए मेंटरशिप प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को कृषि के ही समान, टेलीविजन और रेडियो पर चैनल शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिससे अनुभवों को साझा किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत एक बड़ी युवा आबादी वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। यहां के लोगों का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब विकास के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। पिछले दो वर्षों में सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए न केवल प्रयास किए हैं बल्कि स्वरोजगार और विकास के लिए अनुकूल माहौल भी बनाने का प्रयास किया है। ❑